ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवक

*566. **प्रो0 एम0 एम0 अग्रवालः** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरो जगार युवकों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रोजगार हेतु कोई नई योजना आरंभ करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा0 रघुवंश प्रसाद सिंह)ः (क) से (ग़) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शिक्षित ग्रामीण युवाओं के बीच व्याप्त बेरोजगारी दर के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है। ग्रामीण युवाओं सहित बेरोजगारी संबंधी जानकारी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा उनके नमूना सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्र की जाती है, जिसके परिणाम वर्ष 1999-2000 से संबंधित है। एनएसएसओ के 61 वें दौरे के सर्वेक्षण, जिसके परिणाम जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगे, से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या की नवीनतम स्थिति का पता चलेगा।

2. 10वीं योजना में 2002-2007 के दौरान 500 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की परिकल्पना है। रोजगार की संभावना बनाने के लिए 10वीं योजना में विकास के लिए सामाजिक वानिकी, पशुपालन, मत्स्यपालन, बागवानी और इनसे संबंधित क्षेत्रों सहित कृषि तथा लघु एवं मध्यम उद्योग, निर्माण, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे- श्रम प्रधान क्षेत्रों और उप क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है ।

3. रोजगार सृजन एक बहुक्षेत्रीय मुद्दा है जिसमें अनेक मंत्रालय / क्षेत्र शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और संपूर्ण रोजगार योजना नामक रोजगार सृजन की दो बडी योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। सरकार ने पूरक मजदूरी रोजगार पैदा करने के लिए देश के 27 राज्यों के 150 अत्यधिक पिछड़े जिलों में आवश्यकता आधारित आर्थिक, सामाजिक और सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करके खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हुए इन जिलों में काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम नामक एक नई मजदूरी रोजगार योजना आरंभ की

है । यह योजना ऐसे गारीब ग्रामीणों के लिए उपलब्ध होगी जिन्हें मजदूरी रोजगार की आवश्यकता है और शारीरिक अकुशल कार्य करने के इच्छुक हैं। कार्यक्रम के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लाई जाएगी जिसके लिए विधेयक संसद में पेश किया गया है और यह स्थायी समिति के पास लंबित है।

Educated unemployed youths in rural areas

*566. PROF. M.M. AGARWAL: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Government are aware of the fact that the number of educated unemployed youths in rural areas in the country is increasing;

(b) if so, whether Government proposed to introduce any new scheme for regular employment in rural reas in the country; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH) (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The Ministry of Rural Development has not conducted any Survey on the prevalent unemployment rate among the educated rural youth. The information on unemployment including rural youths in compiled by the National Sample Survey Organisaion (NSSO) through their sample surveys, the results of which relates to the year 1999-2000. The 61st round survey of the NSSO the results of which will be available shortly will reveal the latest status of the number of educated unemployed youth in the rural areas of the country.

2. The Tenth Plan envisages creation of 50 million employment opportunities during 2002-02. To create employment potential the Tenth Plan has identified the labour intensive sectors and sub-sectors for development such as agriculture, including social forestry, animal husbandry, fishing, horticulture and related areas and small and medium industries, construction, tourism, information technology, financial sector, education and health.

† Original notice of the question was received in Hindi.

3. Employment generation is a multisectoral issue involving several Ministries/Sectors. The Ministry of Rural Development is implementing two major employment generation Schemes namely Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY) and Sampoorna Gramin Rozgar Yojana (SGRY). The Government have also launched a new wage employment Scheme namely National Food For Works Programme (NFFWP) in 150 most backward districts of 27 States of the country to generate supplementary wage employment and providing food security through creation of need based economic, social and community assets in these districts. The NFFWP will be open to the rural poor who are in need of wage employment and desire to do manual unskilled work. This programme will be replaced by the National Rural Employment Guarantee Scheme, the Bill for which is introduced in the Parliament and pending with the Standing Committee.

प्रो0 एम0एम0 अग्रवालः सभापति जी , आज हमारे देश में बेरोजगार युवको की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। हमारे देश में उदारीकरण लागू हुए भी तेरह वर्ष हो चुके है, फिर भी अभी तक इस तरफ कोई अच्छा काम नहीं हुआ है और असफल हो रहे है। यही कारण है कि बेरोजगार युवकों में असंतोष फैल रहा है, यही कारण है कि युवक कानून को अपने हाथ में ले रहे है और उनकी गतिविधियों में फर्क आ रहा है। ऎसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि वे बेरोजगार युवकों को रोजगार दें, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दें। मंत्री महोदय यह बताएं कि क्या वे बेरोजगारी भत्ता देने का कोई प्रयोग कर रहे है।

डा0 रघुवंश प्रसाद सिंहः सभापति जी, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी है ...(**व्यवधान**)...। बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी हटाने के लिए हम दो तरह से काम रहे हैं। महोदय, नम्बर एक तो हम बड़े पैमाने पर वेज एम्प्लोएमेटं चला रहे हैं। एक संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और फूड फोर वर्क भी देश के डेढ़ सौ पिछड़े जिलों में चला रहे हैं। इसमें दोनों मिलाकर, करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च करके लोगों को रोजगार दे सकेंगे। गावं में लोगों को काम देकर मजदूरी मिले, वे अपना जीवन यापन कर सकें, इसकी व्यवस्था की गई है। सभापति जी, इसके पश्चात् स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना है। सभी को रोजगार देना संभव नहीं है, इसलिए स्वंय सहायता समूह बनाकर, जिसमें महिलाएं, आदिवासी, अनुसूचित जाति, डाउन ट्रोडन पोजीशन में जो सभी तरह के लोग रह रहे हैं, उन सभी तरह के लोगं को ट्रेनिंग देकर, उनका बैंक से लिंकेज कराकर, उन्हें सब्सिडी देकर, उनके द्वारा उत्पादित सामान को देश –विदेश में बिकवाने का प्रबंध किया जा रहा है। इससे स्वरोजगार के जरिए भी बेरोजगारी खत्म हो सकेगी। सभापति जी, एम्पलोएमेंत गारंटी स्कीम वाला एक कानून लोकसभा में स्टैण्डिग कमेटी के पास लंबित है। हम चाहते है कि वह इसी सत्र में लागू हो जाए। इससे इस साल के हमारे कॉमन मिनिमम

प्रोग्राम में जो कहा गया है कि साल में सौ दिन के रोजगार की गांरटी का कानून पास होगा, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, इसके पास होने से बेरोजगारी पर एक बड़ा भारी आघात होगा और लोगों को रोजागार मिलेगा।

श्री सभापति : बेरोजगारी खत्म हुई हो या नहीं हुई हो , लेकिन क्वेश्चन का समय खत्म हो गया है ।

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Threats to Bus passengers from Srinagar to Muzaffarabad

*561. SHRI RAM NATH KOVIND:
SHRI S.S. AHLUWALIA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state.

(a) whether terrorists in Jammu & Kashmir had threatened to kill the passengers who booked for the inaugural bus travel from Srinagar to Muzaffarabad on 7th April, 2005;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether identity of the passengers for the inaugural bus journey from Srinagar were leaked out to terrorists in advance;

(d) whether his Pakistani counterpart has been urged upon to investigate into the source of leakage at his end;

(e) if so, response from Pakistan thereto;

(f) if not, the reasons therefor; and

(g) the measures taken, if any, to ensure pre-journey confidentiality of passengers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SRIPRAKASH JAISWAL): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) In the threat faxed on March 30, 2005 to a local news agency in Srinagar four terrorists fronts, *viz.* Save Kashmir Movement (SKM), Al Aafreen, Al Nasreen and Farzandan-e-Millat had warned people not to travel in the bus traveling from Srinagar to Muzaffarabad. Enclosed with the fax was the list of the 40 prospective passengers from our side.